अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संघों को सुविधायें

1932. **श्री नत्था सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की यूनियनों, एसोसिएशनों और फैडरेशनों को वे सुविधायें दी गई थीं जो मान्यता प्राप्त जनरल यूनियनों को मिलती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उन सुविधाओं का देना बन्द कर दिया है यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों ने इन यूनियनों आदि को सुविधाएं बहाल करने के लिये कोई अपील की है, यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसद सदस्यों ने अपने जिन पत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशनों, यूनियनों आदि को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया था उन पत्रों का उत्तर भेज दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरकार की नीति के अनुसार जाति, वंश, धार्मिक सम्प्रदाय के आधार पर बनाई गई एसोसिएशन आदि को मान्यता नहीं दी जाती है ।

Industrial Development in Himachal Pradesh

1933. SHRIMATI USHA MALHOTRA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the target of industrial development in Himachal Pradesh has not been achieved during the last three years;

(b) whether Government propose to set up a big industry in Himachal Pradesh in the near future; and

(c) if so, what are the detail* thereof?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) No shortfall in plan expenditure is expected against the overall plan outlay approved by the Planning Commie-sion during the first three years of the Sixth Plan viz. 1980-83 for the development of large, medium village and small industries in Himachal Pradesh in the State Sector.

(b) and (c) The Cement Corporation of India have set up a cement factory at Rajban in Himachal Pradesh with a capacity of 2 lakh tonnes per annum. At present no proposal is under consideration to set uP a big industry in Himachal Pradesh in the Central Sector.

Organising of Lottery ln Pondicherry

1934. SHRI V. P. M. SAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the period for which the lottery is being run in the Union Territory of Pondicherry and to whom the licence for the purposes has been given;

(b) what is the amount earned (month-wise) by the Pondicherry Administration and also cost of the tickets sold out (month-wise) durine the last three years;